10 साल में दोगुना हुआ युवाओं का पलायन

ऐसोचैम के सर्वे में खुलासा, सीएम को दिए सुझाव

■ एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ

यूपी में नौकरी न मिलने की वजह से युवाओं का पलायन सबसे ज्यादा Q है। हाल यह है कि देश में सबसे ज्यादा यूपी से युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य जाते हैं। बीते 10 साल में यह संख्या दोगुनी हुई है। यह तथ्य सामने आया है एसोचैम के सर्वे में।

एसोचैम ने यह पलायन रोकने के लिए योगी सरकार को सुझाव भी दिए हैं। इसी सिलसिले में एसोचैम के अध्यक्ष संदीप जजोडिया, महासचिव डीएस रावत और टारी की डायरेक्टर क्षमा वी कौशिक ने बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरान सीएम को सुझाव पत्र भी दिया गया।

एसोचैम करेगा स्टैंडअप कॉन्फ्रेंस

एसोचैम के अध्यक्ष संदीप जजोडिया ने कहा कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में लखनऊ में महिला उद्यमियों क ी स्टैंडअप कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पर सहमति दी है। एसोचैम ने प्रदेश की नई उद्योग नीति में सरकार के साथ सहयोग करने की भी इच्छा जताई है। इसके लिए हम जल्द एक समिति का गठन करेंगे। यह समिति 15 जुलाई तक राज्य सरकार को अपने सुझाव सौंप देगी।

10 साल में 58.34 लाख युवा गए

रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से 2011 के बीच 20-29 साल के 58 लाख 34 हजार युवाओं ने पलायन किया है। जबकि 1991 से 2001 के बीच 29 लाख 55 हजार युवा प्रदेश से गए।

ऐसे रुकेगी यूथ पावर

यूपी से युवाओं का पलायन रोकने के लिए एसोचैम और थॉट आर्बिट्रेज रिसर्च इंस्टिट्यूट (टारी) ने ये सुझाव दिए हैं।

- पलायन प्रभावित क्षेत्रों में विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जिला आधारित नीतियां बनें।
- पूर्वांचल से सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है, ऐसे में यहां बड़े पैमाने पर कौशल विकास केन्द्र बनें।
- स्टार्टअप नीति पर ध्यान दिया जाए।
- औरैया और झांसी में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का विकास, दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र की स्थापना,आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर आईटी निवेश क्षेत्र बने।

पलायन रोकने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम उन सेक्टर्स पर हों, जिनमें श्रमिकों को राज्य के बाहर काम मिल रहा है। इनमें मेन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट (ड्राइवर) शामिल हैं।-डीएस रावत, महासचिव, एसोचैम

Hindustan City Edition (Lucknow) 8 June, 2017

पलायन रोकने को नीति बने:एसोचैम

लखनऊ | कार्यालय संवाददाता

उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा संख्या में लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं। हाल के दशकों में यह सिलसिला और तेज हुआ है।

वर्ष 2001 से 2011 के बीच 20 से 29 साल आयु वर्ग के 58 लाख 34 हजार लोगों ने रोजगार के लिये दूसरे स्थानों पर पलायन किया, जबकि 1991 से 2001 के बीच यह आंकड़ा 29 लाख 55 हजार था। इस तरह से पलायन का आंकड़ा लगभग दोगुना हो चुका है। इसे रोकने के लिये पलायन से प्रभावित क्षेत्रों में क्षमता विकास तथा रोजगार सृजन की जिला आधारित नीतियां बनाई जानी चाहिये।

यह बात द असोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) के अध्यक्ष संदीप जजोदिया ने कही। वह बुधवार को गोमतीनगर स्थित होटल ताज में प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान एसोचैम और थॉट आर्बिट्रेज रिसर्च इंस्टीट्यूट (टारी) द्वारा पंचवर्षीय विकास एजेंडा ह्यएक्शन प्लान फॉर द न्यू गवर्नमेंटह्ल पेश किया। एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने कहा कि कौशल विकास कार्यक्रम खासकर उन कार्यों पर केंद्रित होना चाहिये जिनसे श्रमिकों को अपने राज्य के बाहर काम मिलता है।

कौशल विकास से संवरेगी बेरोजगारों की तकदीर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : रोजगार के कम अवसर होने के कारण गरीब युवाओं को प्रदेश छोड़ना पड़ता है, लेकिन इन्हीं युवाओं को कुशल बना दिया जाए तो कम से कम माइग्रेशन के बाद भी वे गरीब नहीं रहेंगे। इसी तरह प्रदेश में कृषि उपज में आ रही कमी को रोकते हुए किसानों को बेहतर मूल्य दिलाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभाला जा सकता है तो लघु व मध्यम उद्योगों के सहारे सूबे की औद्योगिक रीढ़ भी मजबूत की जा सकती है। कुछ ऐसे ही सुझाव बुधवार को दि एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिए।

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पत्रकारों के मुखातिब हुए एसोचैम के अध्यक्ष संदीप जजोदिया, महासचिव डीएस रावत तथा थॉट आर्बिट्रेज रिसर्च इंस्टीट्यूट (टारी) की निदेशक क्षमा वी.कौशिक ने बताया कि प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने छह सूत्रीय एजेंडा प्रस्तुत किया है। संगठन पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि यह एजेंडा उन क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया तेज करने में मदद करेगा, जिनसे राज्य के विकास में तीव्रता लाई जा सकती है। पदाधिकारियों ने बताया कि रिसर्च के बाद पेश की गई रिपोर्ट में प्रदेश को प्रखर अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के लिए क्षमता विकास, कृषि, औद्यानिकी, हस्तशिल्प, हथकरघा तथा चमड़ा उत्पादों पर खास जोर देने की बात कही गई है।

पहल

- **प्रदेश की बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री को एसोचैम ने सौंपे सुझाव**
- **छह सूत्रीय एजेंडे में कौशल विकास, कृषि व औद्योगिक विकास पर है जोर**

जल्द आएगी औद्योगिक नीति

एसोचैम व टारी के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश की औद्योगिक नीति जल्द लाने की बात कही है। प्रतिनिधियों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया है कि पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर कुछ दिनों में इसे नेट पर अपलोड कर सुझाव मांगे जाएंगे। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से इस प्रक्रिया में उनके सुझावों को भी शामिल करने का आग्रह किया है।

रिपोर्ट में सीएम को सुझाव दिया गया कि सबसे ज्यादा पलायन पूर्वांचल के जिलों से हो रहा है, इसलिए कौशल विकास केंद्रों की स्थापना इन्हीं केंद्रों में की जानी चाहिए। साथ ही औरैया व झांसी में एकीकृत औद्योगिक टाउन, दादरी-नोएडा व गाजियाबाद में निवेश क्षेत्र की स्थापना और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे के किनारे आइटी निवेश क्षेत्र बनाने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार को अन्य प्रदेशों की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीतियों का अध्ययन करने की भी सलाह दी गई है, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कदम उठाए जा सकें।

नौकरी के लिए सबसे ज्यादा पलायन यूपी से

लखनऊ (एसएनबी)। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा संख्या में लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं और हाल के दशकों में यह सिलसिला दोगुनी तेजी से बढ़ा है। उद्योग मण्डल एसोचैम द्वारा राज्य की नई सरकार के लिए जारी छह सूत्रीय एजेण्डा में यह तथ्य सामने रखा गया है।

एसोचैम और थॉट आर्बिट्रेज रिसर्च इंस्टीट्यूट (टारी) ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए छह सूत्री एजेंडा 'एक्शन प्लान फॉर द न्यू गवर्नमेंट' में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा संख्या में लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं और हाल के दशकों में यह सिलसिला और तेज हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इसे रोकने के लिए विस्थापन अथवा पलायन से प्रभावित क्षेत्रों में क्षमता विकास तथा रोजगार सृजन की जिला आधारित नीतियां बनाई जानी चाहिए। पूर्वी क्षेत्रों से चूंकि ज्यादा पलायन हो रहा है इसलिए कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना इन्हीं इलाकों में की जानी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से 2011 के बीच 20 से 29 साल आयु वर्ग के 58 लाख 34 हजार लोगों ने रोजगार के लिए दूसरे स्थानों पर पलायन किया। एसोचैम के अध्यक्ष संदीप जजोदिया, महासचिव डी. एस. रावत तथा टारी की निदेशक क्षमा वी. कौशिक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद इस सुझाव पत्र को संयुक्त रूप से जारी किया।

रपट

- एसोचैम ने योगी सरकार के लिए पेश किया छह सूत्री एजेंडा
- पलायन रोकने को जिला आधारित नीतियों की जरूरत
- 2001 से 2011 के बीच 58.34 लाख लोगों ने किया पलायन
- इनमें पूर्वी जिलों के लोगों की संख्या ज्यादा
- पूर्वी जिलों में कौशल विकास योजनाएं तेजी से लागू करने का सुझाव
- जिन स्थानों पर पलायन ज्यादा है वहां उद्योग लगाने का सुझाव

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए पेश किये गये छह सूत्रीय नवोन्मेषी पंचवर्षीय विकास एजेंडे में राज्य के विकास का खाका पेश किया गया है। श्री जजोदिया ने कहा कि असीम संभावनाओं से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश यदि आर्थिक रूप से सशक्त हो तो वह पूरे देश के लिए विकास का इंजन साबित हो सकता है।

आर्थिक सुधारों से ही निकलेगा तरक्की का रास्ता

लखनऊ (ब्यूरो)। उप्र में 2000 के दशक में 20 से 29 वर्ष के 29.55 लाख युवाओं ने नौकरियों के लिए दूसरे राज्यों का रुख किया। 2001 से 2011 के दौरान यह आंकड़ा बढ़कर 58.34 लाख पहुंच गया। इन स्थितियों के लिए केवल सरकार और आबादी को ही कारण नहीं माना जा सकता, बल्कि आर्थिक सुधारों की कमी और निजी क्षेत्र को निवेश के लिए आकर्षित न कर पाना भी बड़ी वजह रही। बुधवार को एसोचैम ने प्रेस वार्ता आयोजित कर यूपी सरकार के लिए 2017 में विकास का एजेंडा सामने रखा। इसमें कृषि और उद्योगों पर अधिक जोर दिया गया है।

रिपोर्ट के बारे में एसोचैम के अध्यक्ष संदीप जाजोड़िया ने बताया कि इसे थॉट आर्बिट्रेज रिसर्च इंस्टीट्यूट (टारी) के साथ मिलकर तैयार किया गया। उन्होंने कहा, यूपी को आगे बढ़ने के लिए हथकरघा और चमड़ा उद्योग पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि यह इसके पारंपरिक क्षेत्र रहे हैं। वहीं पलायन को रोकने के लिए प्रदेश में ही रोजगार के बेहतर विकल्प देने होंगे। ऐसा नहीं किया तो न केवल श्रमिक वर्ग, बल्कि शिक्षित प्रोफेशनल्स भी प्रदेश के विकास में योगदान नहीं दे सकेंगे। कार्यक्रम में टारी की निदेशक क्षमा कौशिक भी मौजूद थीं। उन्होंने गरीबी को प्रदेश के विकास में बाधक बताया। कहा कि औसत आय में इजाफा करने की भी जरूरत है। एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने प्रदेश में कौशल विकास कार्यक्रमों को तेजी से चलाने पर जोर दिया।

एसोचैम ने उत्तर प्रदेश के लिये पेश किया छह सूत्रीय विकास एजेंडा

व.सं, VOL

लखनऊ। आदित्यनाथ के लिये छह सूत्रीय नवोन्मेषी पंचवर्षीय विकास एजेण्डा पेश किया है। यह एजेण्डा प्रदेश की नयी सरकार को उन क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करेगा, जिनसे राज्य के विकास में तीव्रता लायी जा सकती है। द असोसिएटेड चैम्बर्स ऑफकॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री ऑफ इण्डिया (एसोचैम) और थॉट आर्बिट्रेज रिसर्च इंस्टीट्यूट (टारी) ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के लिये एक सु-हजयावरूपी एजेंडा 'एक्शन प्लान फॉर द न्यू गवर्नमेंट' तैयार किया है।

एसोचैम के अध्यक्ष श्री संदीप जजोदिया, महासचिव डी. एस. रावत तथा टारी की निदेशक क्षमा वी. कौशिक ने आज लखनऊ में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में इस सुझाव पत्र को संयुक्त रूप से जारी किया। इस अध्ययन में उत्तर प्रदेश को एक प्रखर अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के लिये जरूरी विभिन्न कदमों को लेकर सुझाव दिये गये हैं। इसमें क्षमता विकास, कृषि, औद्यानिकी, हस्तशिल्प, हथकरघा, चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद क्षेत्रों पर खास जोर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश को एक प्रखर अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के लिये जरूरी विभिन्न कदमों को लेकर सुझाव दिये गये हैं

योगी आदित्यनाथ सरकार के लिये अगले पांच साल का आर्थिक रोडमैप प्रस्तुत करते हुए इस अध्ययन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा संख्या में लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं और हाल के दशकों में यह सिलसिला और तेज हुआ है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच 20 से 29 साल आयु वर्ग के 58 लाख 34 हजार लोगों ने रोजगार के लिये दूसरे स्थानों पर पलायन किया, जबकि 1991 से 2001 के बीच यह आंकड़ा 29 लाख 55 हजार था। इस तरह से पलायन का आंकड़ा लगभग दोगना हो चुका है। अध्ययन के अनुसार इसे रोकने के लिये विस्थापन अथवा पलायन से प्रभावित क्षेत्रों में क्षमता विकास तथा रोजगार सृजन की जिला आधारित नीतियां बनायी जानी चाहिये।

चूंकि पूर्वी क्षेत्रों से ज्यादा पलायन हो रहा है, इसलिये ऐसे कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना इन्हीं इलाकों में की जानी चाहिये। बहरहाल, श्रमिकों के विस्थापन की स्थिति भले ही ज्यादा खराब न हो लेकिन इसकी तीव्रता और इसका कारण बनने वाली राजनीतिक गतिविधियां (उदाहरण के लिये-महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के विस्थापितों को नियमित रूप से निशाना बनाया जाना) चिन्ता का बड़ा कारण हैं।

Hindustan State Edition (Lucknow) 8 June, 2017

रोजगार सृजन की नीतियां बनें:एसोचैम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा संख्या में लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं। हाल के दशकों में यह सिलसिला और तेज हुआ है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच 20 से 29 साल आयु वर्ग के 58 लाख 34 हजार लोगों ने रोजगार के लिये दूसरे स्थानों पर पलायन किया, जबकि 1991 से 2001 के बीच यह आंकड़ा 29 लाख 55 हजार था। इस तरह से पलायन का आंकड़ा लगभग दोगुना हो चुका है। पलायन के क्षेत्रों में क्षमता विकास तथा रोजगार सृजन की जिला आधारित नीतियां बनाई जानी चाहिये।

एसोचैम ने मुख्यमंत्री को सौंपा छह सूत्रीय पंचवर्षीय विकास का एजेंडा

लखनऊ, बुधवार। देश के शीर्ष उद्योग मण्डल एसोचैम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिये छह सूत्रीय नवोन्मेषी पंचवर्षीय विकास एजेण्डा पेश किया है। यह एजेण्डा प्रदेश की नयी सरकार को उन क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करेगा जिनसे राज्य के विकास में तीव्रता लायी जा सकती है। द असोसिएटेड चैम्बर्स ऑफकॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री ऑफइण्डिया एसोचैम और थॉट आर्बिट्रेज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के लिये एक सुझाव रूपी एजेंडा एक्शन प्लान फॉर द न्यू गवर्नमेंट तैयार किया है। एसोचैम के अध्यक्ष संदीप जजोदिया महासचिव डी एस रावत तथा टारी की निदेशक क्षमा वी कौशिक ने आज एक वार्ता में इस सुझाव पत्र को संयुक्त रूप से जारी किया। इस अध्ययन में उत्तर प्रदेश को एक प्रखर अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के लिये जरूरी विभिन्न कदमों को लेकर सुझाव दिये गये हैं। इसमें क्षमता विकास कृषि औद्यानिकी हस्तशिल्प हथकरघा चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद क्षेत्रों पर खास जोर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के लिये अगले पांच साल का आर्थिक रोडमैप प्रस्तुत करते हुए इस अध्ययन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा संख्या में लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं और हाल के दशकों में यह सिलसिला और तेज हुआ है।

यूपी में पलायन रोकने के लिये रोजगार सृजन की नीतियां बनाई जानी चाहिये

लखनऊ। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा संख्या में लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं। हाल के दशकों में यह सिलसिला और तेज हुआ है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच 20 से 29 साल आयु वर्ग के 58 लाख 34 हजार लोगों ने रोजगार के लिये दूसरे स्थानों पर पलायन किया, जबकि 1991 से 2001 के बीच यह आंकड़ा 29 लाख 55 हजार था। इस तरह से पलायन का आंकड़ा लगभग दोगुना हो चुका है। इसे रोकने के लिये पलायन से प्रभावित क्षेत्रों में क्षमता विकास तथा रोजगार सृजन की जिला आधारित नीतियां बनाई जानी चाहिये। यह बात द असोसिएटेड चौम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचौम) के अध्यक्ष संदीप जजोदिया ने कही। वह बुधवार को गोमतीनगर स्थित होटल ताज में प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान एसोचौम और थॉट आर्बिट्रेज रिसर्च इंस्टीट्यूट (टारी) द्वारा पंचवर्षीय विकास एजेंडा श्एक्शन प्लान फॉर द न्यू गवर्नमेंटश पेश किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को एक प्रखर अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के लिये जरुरी विभिन्न कदमों को लेकर सुझाव दिये गये हैं। इसमें क्षमता विकास, कृषि, औद्योगिकी, हस्तशिल्प, हथकरघा, चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद क्षेत्रों पर खास जोर दिया गया है। एसोचौम के महासचिव डीएस रावत ने कहा कि कौशल विकास कार्यक्रम खासकर उन कार्यों पर केंद्रीत होना चाहिये, जिनसे श्रमिकों को अपने राज्य के बाहर काम मिलता है। इनमें निर्माण, संगठित खुदरा व्यवसाय एवं परिवहन शामिल है। इससे उन्हें प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ मिलने में मदद मिलेगी। टारी की निदेशक क्षमा वी. कौशिक ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक राज्य बना हुआ है, लेकिन कम उत्पादकता तथा ज्यादा आबादी की वजह से फसल का बहुत कम ही आधिक्य उपलब्ध रह पाता है।

रोजगार के लिए यूपी से हो रहा पलायन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा संख्या में लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं और हाल के दशकों में यह सिलसिला दोगुनी तेजी से बढ़ा है। उद्योग मण्डल एसोचैम द्वारा राज्य की नई सरकार के लिए जारी छह सूत्रीय एजेण्डा में यह तथ्य सामने रखा गया है।

एसोचैम और थॉट आर्बिट्रेज रिसर्च इंस्टीट्यूट (टारी) ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए छह सूत्री एजेंडा 'एक्शन प्लान फॉर द न्यू गवर्नमेंट' में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा संख्या में लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं और हाल के दशकों में यह सिलसिला और तेज हुआ है।

रिपोर्ट के अनुसार इसे रोकने के लिए विस्थापन अथवा पलायन से प्रभावित क्षेत्रों में क्षमता विकास तथा रोजगार सृजन की जिला आधारित नीतियां बनाई जानी चाहिए। पूर्वी क्षेत्रों से चूंकि ज्यादा पलायन हो रहा है इसलिए कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना इन्हीं इलाकों में की जानी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से 2011 के बीच 20 से 29 साल आयु वर्ग के 58 लाख 34 हजार लोगों ने रोजगार के लिए दूसरे स्थानों पर पलायन किया जबकि 1991 से 2001 के बीच यह आंकड़ा 29 लाख 55 हजार था। इस तरह से पलायन का आंकड़ा लगभग दोगुना हो चुका है। एसोचैम के अध्यक्ष संदीप जजोडिया, महासचिव डी. एस. रावत तथा टारी की निदेशक क्षमा वी. कौशिक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज मुलाकात के बाद प्रेस कांफ्रेंस में इस सुझाव पत्र को संयुक्त रूप से जारी किया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री को यह सुझाव-पत्र भेंट भी किया गया। रावत ने कहा ''प्रदेश से रोजगार के वास्ते पलायन रोकने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम खासकर उन कार्यों' पर केन्द्रित होना चाहिए, जिनसे श्रमिकों को अपने राज्य के बाहर काम मिलता है। इनमें निर्माण, संगठित खुदरा व्यवसाय एवं परिवहन (वाहन चालक) शामिल है।

◉ जिला आधारित नीतियां बनाने की जरूरत : एसोचैम